वक्त आपका है चाहो तो सोने में उड़ा दो या फिर सोना बना डालो।
– अज्ञात

मजदूरों में फैली घबराहट

शहरों से समाज के कमजोर वर्ग के पलायन को लेकर सरकार की चिंता वाजिब है। उसकी यह आशंका भी निराधार नहीं है कि सोशल मीडिया पर आई फर्जी खबरों और अफवाहों ने मजदूरों में घबराहट पैदा की, जिससे वे दिल्ली तथा अन्य शहरों से पैदल ही अपने गांव के लिए निकल पड़े।

अमन गुप्ता।

कोरोना वायरस से संबंधित खबरों को नियंत्रित करने को लेकर सरकार का आग्रह चिंताजनक है। लॉकडाउन से प्रभावित मजदूरों–कामगारों के संबंध में केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर कीं। अपनी स्टेटस रिपोर्ट में उसने लॉकडाउन की घोषणा के बाद मजदूरों में फैली घबराहट के लिए कई सामाजिक–आर्थिक कारणों को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन उसका मानना है कि पारंपरिक मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य सूचना माध्यमों से दी गई गलत सूचनाओं के कारण हालात ज्यादा बिगड़े। इसलिए उसने कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की कि कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी खबर को प्रसारित करने से पहले सरकारी तंत्र से उसकी पुष्टि करा ली जाए।

गनीमत है कि कोर्ट ने सरकार की इस बात को नहीं माना और 24 घंटे के भीतर उसे एक ऐसा पोर्टल बनाने को कहा, जिससे लोगों को बीमारी से जुड़ी सारी सूचनाएं और जानकारियां मिल सकें। शहरों से समाज के कमजोर वर्ग के पलायन को लेकर सरकार की चिंता वाजिब है। उसकी यह आशंका भी निराधार नहीं है कि सोशल मीडिया पर आई फर्जी खबरों और अफवाहों ने मजदूरों में घबराहट पैदा की, जिससे वे दिल्ली तथा अन्य शहरों से पैदल ही अपने गांव के लिए निकल पड़े। लेकिन इस गड़बड़झाले को रोकने का यही तरीका अगर सरकार की समझ में आता है कि वह खबरें लेने–देने का काम अपने हाथ में ले ले, तो उसे अपनी इस समझ पर पुनर्विचार करना चाहिए। संकट के दौर में लोग हर तरह की खबरें जानना चाहते हैं, सिर्फ वही नहीं जो सरकारी तंत्र बताना चाहता है। सरकारी अमला अगर इतना भी कर ले जाए कि सरकार के स्तर पर हुए फैसलों की जानकारी लोगों तक पहुंचा दे, तो इसे उसकी सफलता समझा जाना चाहिए। किसी खास मुद्दे को लेकर समाज में कहां क्या घटित हो रहा है, इसके सारे ब्यौरे पता करना और बताना उसके बूते से बाहर है। किसी के आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं और उसके रोजमर्रा के जीवन को वे किस तरह प्रभावित करने जा रही हैं, यह पता करना और बताना मीडिया का काम है। मीडियाकर्मी इसके लिए प्रशिक्षित हैं, उनके पास इसके लिए एक विस्तृत ढांचा है और उनका संस्थान सारी खबरों की पूरी जवाबदेही लेता है। अगर कोई मीडिया संस्थान अपनी खबरों को लेकर अगंभीर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान हैं। इस इतिहास–सिद्ध रास्ते को छोड़कर अगर महामारी से जुड़ी खबरों के लिए सिर्फ सरकारी स्रोतों पर निर्भरता बना दी जाती है तो इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। मसलन यह कि अफवाहों और फेक न्यूज की आपूर्ति के साथ–साथ इसकी मांग भी बढ़ सकती है।

ऐसा हुआ तो सच और झूठ का फर्क खत्म हो जाएगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। मामले का सैद्धांतिक पक्ष यह है कि सरकार द्वारा किसी संकट को सामने रखकर खबरों को अपने हाथ में ले लेना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। आपात स्थितियों में मीडिया वैसे भी सरकार के साथ समझदारी बनाकर चलता है।

धर्म-दर्शन

अकेला करना पड़ा

अशोक वोहरा।

नौकरी शुरू करने के बाद शहर में अपना परिवार रखना ही नहीं, गांव में रह रहे अपने भाइयों को आगे पढ़ाना, बहनों की शादी कराना, ससुराल में दामाद के रूप में बेटे की जिम्मेदारी संभालना। सूची बहुत लंबी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ अकेला करना पड़ा, पर जो कुछ उनके हिस्से आया उसका आर्थिक और भावनात्मक बोझ इतना तो था ही कि वह दूसरा कुछ नहीं सोच पाए, सिवाय अपने लेखकीय दायित्वों के। हस्ती का जो थोड़ा–बहुत हिस्सा बचता था उस पर गांव के हनुमान जी का कब्जा था। समझ सकते हैं कि अपने निजी सपनों के लिए इन सबके बीच कोई गुंजाइश नहीं रह जाती थी। दौलत, शोहरत, पद, पुरस्कार जैसी मृग मरीचिकाएं वैसे भी उन जैसों को अपनी जद में लेने का माद्दा नहीं रखतीं। बच्चों को प्यार भरपूर दिया और उतना ही काफी मानते रहे। फिर यही सब करते हुए एक दिन दुनिया से विदा भी ले ली।

संपादकीय

अवांछित तत्व बन गए

महीने भर से क्रूज लाइनर्स को लेकर जैसी खबरें आ रही हैं, उन्हें सुनकर एक ही बात दिमाग में आती है कि स्वर्ग को नरक बनते देर नहीं लगती। खुले समुद्र में तैरते पांच से आठ हजार यात्रियों और चालक दल वाले ये सुपर–रिच जगमग शहर 21वीं सदी में पूरी दुनिया के नव–धनाढ्यों का संचित स्वप्न माने जाते रहे हैं। लेकिन अभी हाल यह है कि कोई भी देश इन्हें अपने बंदरगाह पर खड़ा नहीं देखना चाहता। वह भी नहीं, जिसके नागरिक इन पर बहुसंख्या में हों। तीन लाख टन तक पानी विस्थापित करने वाले ये विशाल टूरिस्ट जहाज मौज–मस्ती के लिए बने होते हैं। कोविड–19 जैसी जानलेवा संक्रामक बीमारी के मरीजों की देखरेख की बात ही छोड़िए, इमर्जेंसी तक पहुंची आम बीमारियों के इलाज की व्यवस्था भी इनमें नहीं होती। इसीलिए माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के झटके से उबरना कोई 50 अरब डॉलर (3800 अरब रुपये) के सालाना टर्नओवर वाली इस इंडस्ट्री के लिए खासा मुश्किल रहेगा।

अभी पूरी दुनिया में 38 बड़ी क्रूज शिपिंग कंपनियां कुल 277 क्रूज लाइनर्स का संचालन करती हैं। इनमें से 15 फिलहाल समुद्र में ही इधर–उधर भटकते हुए कोई ऐसा बंदरगाह तलाश रहे हैं, जो उन्हें अपने यहां लंगर डालने की मंजूरी दे दे। लाखों रुपया खर्च करके इन पर छुट्टियां बिताने पहुंचे विभिन्न देशों के सम्मानित नागरिक अचानक हर देश के लिए अवांछित तत्व बन गए हैं। एक क्रूज लाइनर खड़ी हालत में भी 77 ट्रकों के बराबर धुआं छोड़ता है, लिहाजा जेब के अलावा पर्यावरण के लिए भी यह कोई कम बड़ी सजा नहीं है। लेकिन दुनिया के एक छोटे हिस्से की बढ़ती अमीरी को देखते हुए लगता नहीं कि आगे भी इसका कुछ बिगड़ने वाला है।

लेकिन इसके साथ ही यह प्रश्न भी उठेगा कि संविधान लागू करने के सत्तर साल बाद भी भारत की बड़ी जनसंख्या की बुनियादी जरूरतें आखिर क्यों नहीं पूरी की जा सकीं?

अहम सवाल भी उठाए

उमेश चतुर्वेदी।

कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस लॉकडाउन का सहारा लिया गया है, वह पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर भारत के लिए यहां के निवासियों की वजह से ही बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। कोलकाता से लेकर मुंबई–अहमदाबाद और दिल्ली–जयपुर से लेकर लखनऊ तक से अपने घरों के लिए पैदल निकले मजदूरों के रेले ने इस लड़ाई को चुनौतीपूर्ण तो बनाया ही है, नीति निर्माताओं और राज–व्यवस्था पर कुछ अहम सवाल भी उठाए हैं। अपने–अपने गांवों के लिए निकली इस भीड़ के बारे में कहा जा रहा है कि इसे बरगलाया गया। कोई यह भी कह सकता है कि इन लोगों ने अफवाहों पर भरोसा कर लिया। लेकिन इसके साथ ही यह प्रश्न भी उठेगा कि संविधान लागू करने के सत्तर साल बाद भी भारत की बड़ी जनसंख्या की बुनियादी जरूरतें आखिर क्यों नहीं पूरी की जा सकीं? समाज के निचले पायदान के लोगों को शैक्षिक और आर्थिक स्तर पर इतना सशक्त क्यों नहीं बनाया जा सका कि वे अफवाहों को नकारते हुए अपनी सामाजिक चुनौतियों को समझ सकें?

देशव्यापी लॉकडाउन की अचानक घोषणा का मकसद था कि जो जहां है, वही ठहर जाए और संचारी कोरोना वायरस को बांधा जा सके।

वैसे भी भारत जैसे देश में, जहां अफवाहों पर दंगे भड़क उठते हैं, लंबे धरने और आंदोलन शुरू हो जाते हैं, वहां किसी महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन का फैसला पूर्व नियोजित ढंग से करना संभव नहीं है। लेकिन जिस आशंका के मद्देनजर देशबंदी की अचानक घोषणा की गई थी, सड़कों पर भूखे–प्यासे उतरे मजदूरों के हुजूम ने उसे हकीकत में बदल दिया है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कहना सही ही है कि मजदूरों की आवाजाही से महामारी को थामने के मकसद पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि यह सभी मान रहे हैं कि हजार किलोमीटर तक की दूरी पैदल नापना लोगों का जज्बा कम, मजबूरी ज्यादा है। प्रधानमंत्री द्वारा देशबंदी की घोषणा करने के पहले ही राज्य सरकारों ने अपने यहां बंदी की घोषणा शुरू कर दी थी। अरविंद केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ ने जहां दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तीन–तीन दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था, वहीं हरियाणा सरकार ने भी बाजार बंद कर दिए थे। उत्तराखंड भी इस राह पर बढ़ चला था। राजस्थान और पंजाब सरकार ने 31 मार्च तक अपने–अपने यहां कर्फ्यू और धारा 144 लगा दी थी। लेकिन किसी भी राज्य ने बंदी के दौरान दिहाड़ी मजदूरों और रेहड़ी–पटरी वालों के लिए रोटी–पानी के ठोस इंतजाम का ऐलान नहीं किया था।

चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की हो या फिर हरियाणा की, कोई भी सरकार हाशिये पर पड़े लोगों और मजदूरों में यह भरोसा पैदा करने में नाकाम रहीं कि उन्हें लॉकडाउन की हालत में खाने–पीने की तकलीफ नहीं होगी। लिहाजा रोजाना कमाने–खाने वाले, झुग्गियों और अमानवीय हालात में रहने वाले हजारों लोगों के सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया। वे बदहवासी से भर उठे। हो सकता है कि इस बीच कुछ अफवाहबाजों ने अफवाहें भी फैलाई हों और अभावों में जिंदगी गुजारने वाले इस तबके के ज्यादातर लोगों को महानगरों में अपनी जिंदगी तबाह होती नजर आने लगी हो।

सूडोकु नवताल-5306

सरल

3				8				9
		8	6		9	5		
6	5			4			7	1
	4						2	
1	2			6			9	8
		6	4		5	8		
9				1				7

Jagrutidaar.com, Bangalore

सूडोकु नवताल -5305 का हल

8	2	4	3	9	7	5	1	6
3	5	6	1	4	2	7	8	9
1	9	7	6	5	8	2	3	4
9	6	2	5	8	3	1	4	7
5	3	1	4	7	9	8	6	2
4	7	8	2	1	6	9	5	3
2	8	3	9	6	1	4	7	5
6	1	5	7	2	4	3	9	8
7	4	9	8	3	5	6	2	1

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

अपना ब्लॉग

समुचित जांच जरूरी

मोहन। ऐसा नहीं होता तो लॉकडाउन की घोषणा के बाद राज्यों की नौकरशाही दिहाड़ी और कम आय वर्ग वाले लोगों को राहत पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करती। वह इस वर्ग को भरोसा जताने में जुट जाती कि देशबंदी में भी उन पर भुखमरी का साया नहीं पड़ने जा रहा। केंद्रीय नौकरशाही भी वक्त पर राज्यों को निर्देश देती कि वे अपने यहां जरूरतमंदों के लिए शिविर और भोजन का प्रबंध करें। तब शायद लोग अपनी जगहों पर रुकते और कोरोना के संकट को बढ़ाने के खतरे को भांप पाते। बहरहाल, अभी तो लोग बीच की स्थिति में हैं। बेहतर होगा कि घर पहुंचने से पहले उनकी मेडिकल जांच और संभावित संक्रमण की पहचान की जाए। देशहित में हमें इस चुनौती का सामना करना ही होगा। इसे भारत के सामाजिक तंत्र की कमजोरी ही कहा जाएगा कि छोटे–बड़े नियोक्ताओं से अपने यहां काम करने वालों को राहत देने की प्रधानमंत्री की अपील भी नाकाम रही।